Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

30 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 6 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया, अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे

Labour Ministry notifies the National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers, to be presided over by the Union Minister for Labour & Employment

SSC • Railway • General

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि उसने श्रम संहिताओं के तहत असंगठित श्रमिकों और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers) के गठन को अधिसूचित कर दिया है, और इसे भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढाँचे के तहत स्थापित ये बोर्ड डिजिटल गिग और प्लेटफ़ॉर्म पेशेवरों को भारत की औपचारिक कल्याण व्यवस्था से जोड़कर एक ऐतिहासिक बदलाव लाते हैं। इन बोर्डों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे, और इनमें केंद्र और राज्य सरकारों, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संघों और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म संघों के प्रतिनिधि होंगे। इन्हें पारंपरिक असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ लाखों गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी को दूर करने हेतु लक्षित कल्याण योजनाएँ तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उनकी सिफ़ारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी, और वे अपनी बैठकों में कार्य-संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों का पालन करेंगे। इनके कार्य हैं: विभिन्न वर्गों के असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफ़ारिश करना; इस संहिता के प्रशासन से उत्पन्न ऐसे मामलों पर, जो उन्हें भेजे जाएँ, केंद्र सरकार को सलाह देना; केंद्र सरकार द्वारा संचालित असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना; राज्य स्तर पर किए जाने वाले अभिलेख-रखरखाव (रिकॉर्ड कीपिंग) कार्यों की समीक्षा करना; निधि और लेखे से होने वाले व्यय की समीक्षा करना; और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330299

2 प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी की: 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित

PM releases the 24th instalment of PM-KISAN from Banaskantha, Gujarat: over ₹18,690 crore transferred to more than 9.34 crore farmers

SSC • Banking • Railway • General

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 24वीं किस्त जारी की, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष के तहत विकसित 521 इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया और 12 बागवानी क्लस्टरों का उद्घाटन भी किया। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम-किसान योजना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि वाले सभी भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता देना है: पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में मिलती है, जिसमें भूमि अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन होता है और राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है। कुल लाभ का लगभग 25% महिला लाभार्थियों को जाता है; 23वीं किस्त तक महिला किसानों को इस योजना के तहत ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी थी, और लगभग हर चार में से एक लाभार्थी महिला किसान है। इस किस्त पर PIB की पृष्ठभूमि सामग्री (बैकग्राउंडर) के अनुसार भुगतान प्रायोजक बैंकों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर योजना के समीक्षा तंत्र की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330395

3 सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया; पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल होंगे अध्यक्ष

Government constitutes the High Level Committee on Banking for Viksit Bharat, with former Central Vigilance Commissioner Suresh N. Patel as Chairman

SSC • Banking • General

वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2026-27 में इस समिति के गठन की घोषणा की थी। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल समिति के अध्यक्ष होंगे; शिरीष चंद्र मुर्मू (उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), पद्मजा चुंदरू (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक) और एन. एस. विश्वनाथन (पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) इसके सदस्य होंगे, और वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल छह महीने होगा। इसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) हैं: वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और प्रुडेंशियल मानदंडों का आकलन करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान कर उन्हें भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए उपयुक्त रूप से अपनाना, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने का रोडमैप देना; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित बैंकों के मौजूदा नियामक और कानूनी ढांचे की समीक्षा करना, और दक्षता लाने तथा विकसित भारत के लिए बैंकिंग में कारोबार करने में सुविधा हेतु सुधार सुझाना; विकास वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करना, और साख वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण स्रोतों और सक्षम तंत्र पर सिफारिशें करना; व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत में अंतरों की जांच करना और सतत विकास के लिए निजी निवेश बढ़ाने हेतु नीतिगत विकल्प सुझाना; साइबर जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के साथ बैंकिंग संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल नवाचार का रोडमैप तैयार करना, और बैंकिंग क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु प्रतिभा अधिग्रहण और क्षमता निर्माण की रणनीति सुझाना; प्राथमिक क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा कर उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और समन्वय का आकलन करना; और भारत सरकार द्वारा समिति को सौंपे गए किसी अन्य विषय पर सिफारिशें करना।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330598

4 पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया 1 नवंबर 2026 से वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त

Air Marshal Inderpal Singh Walia, AOC-in-C Eastern Air Command, appointed Vice Chief of the Air Staff from 1 November 2026

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया, एवीएसएम, वीएम को 1 नवंबर 2026 से वायुसेना का उप प्रमुख (वीसीएएस) नियुक्त किया गया है; वर्तमान में वे पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वालिया भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की लड़ाकू विमान शाखा (फाइटर स्ट्रीम) में कमीशन हुए थे और मिग-21, मिग-23, मिग-27, जगुआर और सुखोई-30 एमकेआई के सभी संस्करणों पर योग्य हैं। लगभग चार दशकों के सेवाकाल में उन्होंने कई कमान और स्टाफ नियुक्तियाँ संभाली हैं: उन्होंने अग्रिम पंक्ति के एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन और 'टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' (टीएसीडीई) की कमान संभाली है, और वे वायुसेना स्टेशन बरेली के एयर ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन में उन्नत कमान एवं स्टाफ पाठ्यक्रम और बांग्लादेश में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) का प्रशिक्षण लिया है, भारतीय वायुसेना के वायु स्टाफ निरीक्षण निदेशालय (डीएएसआई) का नेतृत्व किया है, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए रक्षा अताशे के रूप में सेवाएँ दी हैं, और पूर्वी वायु कमान के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर रहे हैं। उनके पास रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन में तीन स्नातकोत्तर डिग्रियाँ हैं, और उन्हें 2008 में वायु सेना पदक (वीएम) और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया था। वे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का स्थान लेंगे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330557

5 सितंबर 2026 तक के मासिक खाते: भारत सरकार की प्राप्तियाँ ₹18,35,422 करोड़ (बजट अनुमान 2026-27 का 50.3%), कुल व्यय ₹25,49,835 करोड़ (बजट अनुमान का 47.7%)

Monthly accounts up to September 2026: Government of India's receipts at ₹18,35,422 crore (50.3% of BE 2026-27), total expenditure at ₹25,49,835 crore (47.7% of BE)

SSC • Banking • General

वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में सितंबर 2026 तक के भारत सरकार के मासिक खातों को समेकित कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। सितंबर 2026 तक भारत सरकार को ₹18,35,422 करोड़ (2026-27 के बजट अनुमान की कुल प्राप्तियों के संगत 50.3%) प्राप्त हुए, जिसमें ₹12,76,088 करोड़ कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध प्राप्ति), ₹4,80,732 करोड़ गैर-कर राजस्व और ₹78,602 करोड़ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ शामिल हैं। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को ₹6,99,409 करोड़ भेजे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹67,658 करोड़ अधिक है। भारत सरकार का कुल व्यय ₹25,49,835 करोड़ (संगत बजट अनुमान 2026-27 का 47.7%) रहा, जिसमें से ₹18,95,288 करोड़ राजस्व खाते में और ₹6,54,547 करोड़ पूंजी खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से ₹6,46,010 करोड़ ब्याज भुगतान पर और ₹2,22,905 करोड़ प्रमुख सब्सिडी पर खर्च हुए।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330455

6 'एट द टॉप, बुर्ज खलीफा' और 'रिसॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा' में ऑनलाइन बुकिंग के लिए यूपीआई की सुविधा शुरू; एनपीसीआई इंटरनेशनल की साझेदारियों के तहत

UPI acceptance enabled for online bookings at 'At the Top, Burj Khalifa' and Resorts World Sentosa under NPCI International's partnerships

SSC • Banking • General

वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि यूएई और सिंगापुर जाने वाले भारतीय पर्यटक अब अपने पसंदीदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ऐप्स का उपयोग करके बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय शाखा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए यूपीआई की सुविधा देने हेतु यूएई और सिंगापुर के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारियों की घोषणा क्रमशः 29 जुलाई 2026 और 9 सितंबर 2026 को की थी। यूएई में NEOPAY और एमार एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी में 'एट द टॉप, बुर्ज खलीफा' के लिए यूपीआई से भुगतान की सुविधा शुरू की गई है, और यह ई-कॉमर्स के लिए यूपीआई अपनाने वाला यूएई का पहला पर्यटन स्थल है। सिंगापुर में प्रमुख पेमेंट संस्थान 'फोमो पे' (FOMO Pay) के सहयोग से यूपीआई की सुविधा 'रिसॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा' तक बढ़ाई गई है, जिसके आकर्षणों में यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, सिंगापुर ओशनेरियम और एडवेंचर कोव वॉटरपार्क शामिल हैं; रिलीज़ के अनुसार 2025 में सिंगापुर में 1.2 मिलियन भारतीय पर्यटक पहुँचे थे। रिलीज़ में याद दिलाया गया है कि 26 जनवरी 2024 को यूपीआई के ज़रिए एफिल टॉवर का टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की गई थी, और बताया गया है कि यूपीआई दस देशों - सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और ग्रीस - में स्वीकार किया जाता है, तथा 30 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान घोषित एक व्यावसायिक समझौते के बाद उज्बेकिस्तान इस सूची में 11वां देश बनने जा रहा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330558

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 MoSPI की 26 अक्टूबर 2026 की घोषणा के अनुसार ASUSE 2027-28 किस अवधि में आयोजित करने का प्रस्ताव है?

(A) अक्टूबर 2027 से सितंबर 2028
(B) जुलाई 2027 से जून 2028
(C) जनवरी 2027 से दिसंबर 2027
(D) अप्रैल 2027 से मार्च 2028

प्र.2 31 अक्टूबर 2026 को एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायु सेना के ____ वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। रिक्त स्थान भरें।

(A) 30वें
(B) 29वें
(C) 27वें
(D) 28वें

प्र.3 PIB की 27 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित CCUS योजना में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई?

(A) 50,000 करोड़ रुपये
(B) 20,000 करोड़ रुपये
(C) 10,000 करोड़ रुपये
(D) 5,000 करोड़ रुपये

प्र.4 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 26 अक्टूबर 2026 को बताया कि झारखंड के 57 स्टेशनों का पुनर्विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है?

(A) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
(B) मॉडल स्टेशन योजना
(C) अमृत भारत स्टेशन योजना
(D) आदर्श स्टेशन योजना

प्र.5 कपास के आयात पर सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की अधिसूचना किस विभाग ने जारी की?

(A) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वाणिज्य विभाग
(B) वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग
(C) वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग
(D) वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग

उत्तर: 1-(D) 2-(B) 3-(B) 4-(C) 5-(C)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।